



जागत



चौपाल से
भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 17-23 जून 2024, वर्ष-10, अंक-9

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ:-8, मूल्य:- 2 रुपए

बिचौलिये मनमाने दाम पर खरीद रहे उपज: 80 वर्ग किलोमीटर में होनी चाहिए सरकार द्वारा रेगुलेटेड एक मंडी

अभी किसानों को 406 वर्ग किमी पर एक मंडी उपलब्ध हो पा रही

आजादी के 75 साल बाद भी किसानों को 30 हजार कृषि मंडियों की दरकार

भोपाल | जागत गांव हमार

आजादी के बाद से अब तक सभी सरकारों यह कहती रही हैं कि किसानों के लिए काम करेंगी, लेकिन आज तक पर्याप्त बाजार की सुविधा तक मुहैया नहीं करा सकी हैं। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि 2006 में आई राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 80 वर्ग किमी क्षेत्र में सरकार द्वारा रेगुलेटेड एक मंडी यानी एपीएमसी होनी चाहिए, लेकिन इस मौजूद समय में 406 वर्ग किमी क्षेत्र में किसानों को एक कृषि मंडी की सुविधा मिल रही है। इसी कारण किसान अपनी उपज औने-पौने दाम पर व्यापारियों और बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस बात की तस्दीक आंकड़ कर रहे हैं। आज भी उन सूबों के किसानों की आय अच्छी है, जहां पर कृषि मंडियों का पर्याप्त जाल बिछा हुआ है। बड़े राज्यों में बात की जाए तो पंजाब में 116 और हरियाणा में 155 वर्ग किमी में एक मंडी की सुविधा उपलब्ध है। यह उस मानक के काफी नजदीक है, जो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने बताया है। इसीलिए उक्त दोनों राज्य किसानों की आय के मामले में सबसे ऊपर नजर आते हैं।

यूपी-बिहार के किसानों की आय कम- जुलाई-2018 से जून-2019 तक के बीच किसानों की आय के लिए हुए सरकारी सर्वे के अनुसार देश में प्रति किसान परिवार औसत आय 10,218 रुपए महीना है। जबकि पंजाब में प्रति किसान परिवार आय 26,701 और हरियाणा में 22,841 रुपए है। बिहार में सिर्फ 7,542 रुपए है, जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। उत्तर प्रदेश में 384 वर्ग किमी पर एक एपीएमसी मंडी है। यहां भी किसान परिवारों की आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम सिर्फ 8,061 रुपए है।

हमें यह आकलन करना चाहिए कि यह कार्य महत्वपूर्ण है। हमारे पास एक नेटवर्क होना चाहिए। क्या हमारा नेटवर्क अपेक्षित परिणाम दे पाया है, क्या यह ठीक से काम कर रहा है या नहीं, जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया था और अगर इसमें कोई कमी है तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है।

शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री

किस राज्य में कितने वर्ग किमी में उपलब्ध है एक मंडी

राज्य	रेगुलेटेड मंडियाँ	दूरी किमी में एक मंडी
आंध्र प्रदेश	318	512
अरुणाचल	19	4408
असम	226	347
चंडीगढ़	01	114
छत्तीसगढ़	187	723
गोवा	08	463
गुजरात	405	484
हरियाणा	285	155
हिमाचल	63	884
झारखंड	201	397
कर्नाटक	564	340
मध्य प्रदेश	557	554
महाराष्ट्र	929	331
मेघालय	02	11215
नागालैंड	19	873
नई दिल्ली	15	99
ओडिशा	535	291
पुदुचेरी	08	70
पंजाब	436	116
राजस्थान	484	707
तमिलनाडु	288	452
तेलंगाना	282	397
त्रिपुरा	21	499
उत्तर प्रदेश	633	384
उत्तराखंड	62	863
पश्चिम बंगाल	537	165
कुल	7085	406



किसान आयोग 2006 में बदला मानक

किसानों की आय बढ़ाने के लिए अप्रैल 2016 में गठित डॉ. अशोक दत्तवर्मा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार देश को 30,000 मंडियों की दरकार है। सरकार को यह रिपोर्ट सितंबर 2018 में सौंपी गई थी। रिपोर्ट में एक जगह कहा गया है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) द्वारा सिफारिश की गई थी कि खेती से 5 किमी की सीमा के भीतर एक बाजार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एक ऐसी दूरी जो एक घंटे के भीतर पैदल या गाड़ी से तय की जा सके। बाद में नए किसान आयोग ने 2006 में इसका मानक बदल दिया। इसमें बताया गया कि 80 वर्ग किमी में एक मंडी की जरूरत है।

हैरान करने वाला आंकड़ा

वर्तमान में देश में एपीएमसी मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) द्वारा रेगुलेटेड मंडियों की कुल संख्या का अगर राज्यवार ब्योरा देखेंगे तो आँख खुल जाएगी। संसद में 31 मार्च 2023 तक की रखी गई एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सिर्फ 7085 कृषि मंडियाँ हैं। जबकि अगर भौगोलिक क्षेत्र और राष्ट्रीय किसान आयोग के मानक के हिसाब से देखा जाए तो यह काफी कम है। हालांकि, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि मंडी के अंतर को पाटने के लिए निजी मंडियों की स्थापना हो रही है। यही नहीं, सरकार किसानों से सीधे थोक खरीद को बढ़ावा दे रही है।

कारण से 5 वर्ग किलोमीटर पर ही एक मंडी होनी चाहिए, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने बहुत दूर न जाना पड़े। माल दुलाई कम लगे। देश में अभी सिर्फ सात हजार कृषि मंडियाँ हैं। मौजूदा समय में 42000 मंडियों की जरूरत है। इस हिसाब से मंडियों की संख्या काफी कम है। सरकार को इसके लिए आगे आना होगा।

देशभर हर्मा, मानवाने कृषि अर्थशास्त्री

एनएससी की गारंटी के साथ ही किसानों को मंडी की भी गारंटी मंगानी पड़ेगी, क्योंकि पर्याप्त मंडियों के बिना किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलना आसान नहीं होगा। बिहार में किसानों की आय कम होने के पीछे एक बड़ी वजह मंडी न होना भी है। किसानों की आय वाली सूची में सबसे नीचे के सूबों में बिहार आता है।

सुयंकर सिंह, पूर्व कृषि मंत्री, बिहार

एपीएमसी रेगुलेटेड मंडियों की राज्यवार सूची पर नजर

राज्य	प्रधान मंडी	उपमंडी	कुल मंडी
आंध्र	193	125	318
अरुणाचल	19	00	19
असम	20	206	226
चंडीगढ़	1	00	01
छत्तीसगढ़	69	118	187
गोवा	01	07	08
गुजरात	213	192	405
हरियाणा	114	171	285
हिमाचल	10	53	63
झारखंड	28	173	201
कर्नाटक	167	397	564
मध्य प्रदेश	259	298	557
महाराष्ट्र	306	623	929
मेघालय	02	00	02
नागालैंड	19	00	19
नई दिल्ली	07	08	15
ओडिशा	54	481	535
पुदुचेरी	03	05	08
पंजाब	152	284	436
राजस्थान	165	319	484
तमिलनाडु	284	00	284
तेलंगाना	95	87	282
त्रिपुरा	21	00	21
उत्तर प्रदेश	251	382	633
उत्तराखंड	24	38	62
बंगाल	22	515	537
कुल	2599	4486	7085

महू वेटेनरी कॉलेज में पहली लैब तैयार, 56 सैपल जांच में से 50 में मिले लक्षण

सावधान! गाय-भैंस, घोड़ा और कुत्तों में भी होता है कैंसर

भोपाल | जागत गांव हमार

महू के पशु चिकित्सा व पशुपालन महाविद्यालय में स्थापित प्रदेश की पहली कैंसर डिटेक्ट लैब से चोँकाने वाली खबर आई है। 20 लाख रुपए से तैयार हुई इन्फ्रारेड डिटेक्टिंग कैमिस्ट्री लैब में पिछले छह महीने में 56 जानवरों के टिश्यू के सैपल की जांच की गई। इनमें से 50 जानवरों में कैंसर के लक्षण मिले हैं। अब तक कुत्तों में लूका, गाय व भैंस में सींग व लिबर और घोड़ों में मुँह व बच्चेदानी का कैंसर मिला है। इन

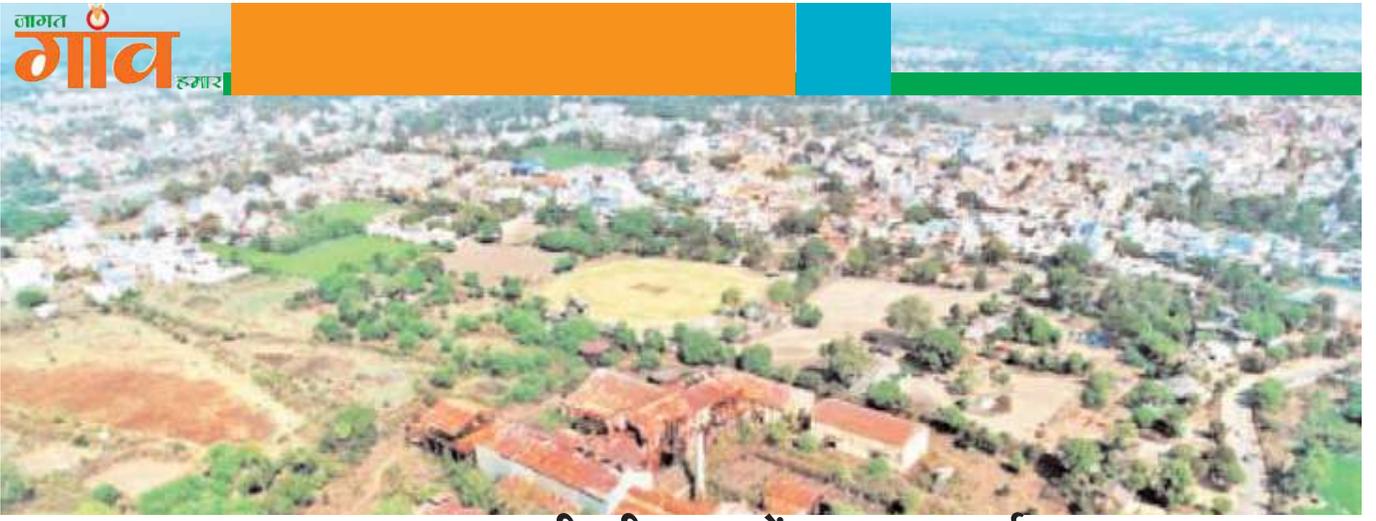
पशुओं में 10 गाय-भैंस, तीन घोड़े व 37 कुत्ते शामिल हैं। लैब खुलने के बाद से पूरे प्रदेश के सैपल महू में ही आ रहे हैं। पहले बीमारी का पता लगाने के लिए पशुओं के सैपल गुजरात भेजे जाते थे। पैथोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष व प्रधान अन्वेषक डॉ. सुप्रिया शुक्ला ने बताया कि प्रदेश से 20 जिला पशु चिकित्सकों को लैब में जांच करने का प्रशिक्षण दिया गया है। सभी अपने जिलों में पशुओं का इलाज कर रहे हैं।



टाइगर, तेंदुआ और हाथी के सैपलों की भी जांच

लैब में कैंसर का प्रकार और स्टेज का भी पता लगाया जा रहा है। यहां पंथर, बाघ, कुत्ता, हाथी, बिल्ली सहित सभी पशुओं की जांच की जा रही है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विवि जबलपुर के कुलपति डॉ. सीताप्रसाद तिवारी के मार्गदर्शन में यह लैब स्थापित हुई। सैपल की जांच डॉ. सुप्रिया शुक्ला, डॉ. निधि श्रीवास्तव, डॉ. दलजीत खन्ना की टीम कर रही है।

लैब की मांग लंबे समय से की जा रही थी। महाविद्यालय में लैब होने से पशु पालकों को पशुओं के कैंसर व अन्य व्याधियों की जांच में सहायता मिलेगी। उनका इलाज भी अब समय पर किया जा सकेगा। डॉ. बीपी शुक्ला, डीन पशु चिकित्सा व पशुपालन महाविद्यालय महू



5772 एकड़ जमीन थी, राजस्व में 4365 एकड़ दर्ज

192 एकड़ प्रबंधन को मिली, बाकी हो गई जायब

भोपाल शुगर मिल की 1215 एकड़ जमीन हो गई लापता

भोपाल | जागत गांव हमार

भोपाल शुगर मिल के पास कुल 5772.22 एकड़ जमीन थी। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार, इसमें से 4,365 जमीन को अतिशेष (सरप्लस) घोषित कर राजस्व के खाते में दर्ज किया गया है, जबकि 192 एकड़ भूमि को मिल प्रबंधन का ही बताया गया। लेकिन, बची हुई 1215 एकड़ जमीन पर किसका अधिकार है, यह कोई नहीं बता रहा। ज्यादातर जमीनों को बेचकर रजिस्ट्रियां कर दी गई हैं। यानी ये किसी और और के के नाम हैं। भोपाल शुगर मिल मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष जमीर बहादुर का कहना है कि मिल जब 2003 में बंद हुई, तब कब्जे नहीं थे। मिल प्रबंधन ने वित्तीय गड़बड़ियां कर पहले मिल को घाटे में बताया। फिर मिल की जमीन अवैध रूप से बेची। अभी सीहोर समेत आसपास के 5 कृषि फार्म की बेशकमती जमीन भूमिफिया के कब्जे में है।

इनके कब्जे में कृषि फार्म

- **भगवानपुरा फार्म:** मिश्रीलाल मनोज राय 100 एकड़, उमेश गुलशन 80 एकड़।
- **सोवन फार्म:** पुरुषोत्तम, सतीश और मोहित पाठक 110 एकड़।
- **लोठिया फार्म:** विनोद, गुड्डा भूरा यादव 100 एकड़, रहल यादव 60 एकड़
- **मोनिया फार्म:** कैलाश त्यागी व परिवार 60 एकड़, रामप्रसाद मेवाड़ा 24 एकड़। (ये नाम सिर्फ बड़े कब्जेधारियों के हैं। भोपाल शुगर मिल यूनिनन ने ये प्रशासन को सौंपे थे।)

964 में सीलिंग में आई मिल की जमीन, फिर तारीख पर तारीख

- **1963-64:** सीलिंग अधिनियम 1960 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। मिल प्रबंधन ने आपत्ति लगाई।
- **22 मई 1987:** सीलिंग अधिकारी ने सुआयना किया और अगस्त 1987 में अतिरिक्त भूमि का विवरण तैयार करने का आदेश दिया।
- **7 सितंबर 1988:** आदेश के खिलाफ मिल प्रबंधन ने भोपाल संभाग के अपर आयुक्त की कोर्ट में आपत्ति (निगरानी) पेश की। कोर्ट ने प्रबंधन की आपत्ति खारिज कर दी।
- **26 मई 1989:** अपर आयुक्त कोर्ट के फैसले के खिलाफ मिल प्रबंधन द्वारा राजस्व मंडल ग्वालियर में दायर अपील को खारिज किया।
- **19 अप्रैल 1989:** सक्षम अधिकारी (सीलिंग) ने मिल की सीहोर के 17 गांवों में मौजूद 5722.22 एकड़ भूमि में से 5547.13 एकड़ भूमि को अतिशेष घोषित किया। इसके खिलाफ मिल प्रबंधन ने जबलपुर हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की।
- **25 जून 2002:** हाई कोर्ट ने मिल की भूमि का निरीक्षण कर सीलिंग

- अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
- **4 जून 2004:** अपर आयुक्त भोपाल संभाग की कोर्ट में मिल द्वारा लगाई गई आपत्ति खारिज की। 2009 में राजस्व मंडल ने भी आपत्ति खारिज की।
- **8 अगस्त 2011:** राजस्व मंडल के आदेश के खिलाफ शुगर मिल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
- **22 दिसंबर 2012:** राजस्व मंडल ग्वालियर ने पूर्व में अपर आयुक्त भोपाल संभाग द्वारा जारी आदेश को यथावत रखा।
- **22 फरवरी 2012:** एसडीएम कोर्ट सीहोर ने विवरणी जारी के दौरान आई आपत्तियों का निराकरण कर मिल को 4365.56 एकड़ भूमि को अतिशेष घोषित कर सरकारी खाते में दर्ज कराने का आदेश दिया।
- **20 मार्च 2012:** एसडीएम कोर्ट व राजस्व मंडल के आदेश के खिलाफ मिल को दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए।

- **29 अगस्त 2019:** हाई कोर्ट में मिल प्रबंधन की ओर से किसी के पेश नहीं होने पर प्रकरण (अदम पैरवी में) खारिज किया गया।
- **1 अक्टूबर 2019:** मिल के आग्रह पर हाईकोर्ट ने केस को सुनवाई पर लिया। पिटीशन को रिस्टोर किया। अंतिम सुनवाई के लिए 16 मार्च 2020 की तारीख तय की। कोरोना महामारी के कारण इसमें देरी हुई।
- **19 जनवरी 2021:** प्रकरण में अंतिम पेशी तय की गई, पर राज्य शासन के महाविधवाका की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो सका। इसके बाद तीन फरवरी 2021 तारीख तय की गई। इसके बाद कोर्ट की ओर से तकरीबन हर महीने तारीख तय की गई, पर अलग-अलग वजहों से पेशी आगे बढ़ती गई।
- **21 फरवरी 2024:** मिल प्रबंधन की ओर से एडवोकेट ने कोर्ट से समय देने की मांग की। इसके लिए तर्क दिया गया कि भोपाल शुगर मिल एनओटीडी कर-पीआओ इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब अस्तित्व में नहीं है।

● शुगर मिल की जमीनों का प्रकरण हाई कोर्ट में विचाराधीन है। जल्द निराकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। कोर्ट में शासन का सभी आवश्यक पक्ष रखा गया है।

- प्रवीण अद्वैयच, कलेक्टर, सीहोर

● 2012 में सरकार ने मिल की जमीन को राजस्व भूमि में दर्ज किया। इसी के बाद भूमिफिया ने कब्जा किया। मिल प्रबंधन ही जमीनों को ठिकाने लगा रहा है।

जयमल सिंह, महामंत्री, जिला इंटक

● जमीनों की कमी के कारण बड़े प्रोजेक्ट इंदौर या आसपास चले जाते हैं। सीहोर शुगर मिल की 5,000 एकड़ से अधिक जमीन सरकार के पास है। इसे इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर डेवलप करें तो भोपाल और आसपास रोजगार और इकोनॉमी दोनों बढ़ेंगे।

राजीव अग्रवाल, अध्यक्ष, ऑल-इंडस्ट्री एसोसिएशन, मंडीदीप

80 हजार से अधिक किसानों को हुआ लाभ

किसानों को पीएम फसल बीमा स्कीम में मिला 101 करोड़

भोपाल | जागत गांव हमार

देश के किसानों को खराब मौसम और अन्य कारणों से हुए फसल नुकसान की भारपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जाती है। इसके तहत किसानों को हुए नुकसान की भारपाई की जाती है। हालांकि यह योजना हमेशा से ही सुखियों में रहती है क्योंकि योजना को लेकर हमेशा किसानों की कोई न कोई शिकायत रहती है। लेकिन अभी एक अच्छी खबर आई है क्योंकि इसमें किसानों को न सिर्फ समय से बल्कि बीमा योजना का पूरा लाभ भी मिला है। किसानों को वर्ष 2023-24 में हुए फसल नुकसान के मुआवजे के तौर पर पीएमएफबीवाई योजना के तहत 101.619 करोड़ दिए गए हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के लगभग 80,644 किसानों को योजना का लाभ मिला है। जिले की उपायुक्त फौजिया तरसुम ने



कहा कि बीमा कंपनी द्वारा वीमिट राशि पहले ही किसानों के खाते में जमा करा दी गई है। उपायुक्त ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि फसल कटाई मूल्यांकन के आधार पर 69,829 किसानों के बैंक खातों में 94.558 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। वहीं स्थानीय आपदा श्रेणी के तहत 18,433 किसानों को 6.242 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा जिन किसानों को कटाई के बाद नुकसान

हुआ है, वैसे 382 किसानों को 81.927 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं।

कई किसानों को नहीं मिला लाभ- कलबुर्गी के उपायुक्त तरसुम ने मॉडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कई किसान ऐसे भी हैं जिनका बैंक खाता आधार से नहीं जोड़ा गया है। ऐसे किसानों की संख्या 281 है जिनके खाते में 35.95 लाख रुपए नहीं भेजे गए हैं। उनके खातों में लिंकेज की प्रक्रिया पूरी करने के बाद पैसे भेज दिए जाएंगे। जिन किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उनकी सूची रैयत संपर्क केंद्र के पास उपलब्ध है। जैसे ही लाभार्थी अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराएंगे, यह राशि तुरंत ही उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। बता दें कि यहाँ के अधिकांश किसान उड़द, सोयाबीन और लाल चना की खेती करते हैं।

दिसंबर 2023 में भी मिले थे पैसे

गौरतलब है कि किसानों को जो राशि ट्रांसफर की गई है, उसमें उस राशि को शामिल नहीं किया गया है जो हाल ही में किसानों को हुए नुकसान के बदले दिए गए हैं। वर्षा आधारित क्षेत्रों में अरहर की खेती करने वाले 1,20,274 किसानों को 83.63 करोड़ रुपए दिसंबर 2023 में दिए गए थे। उन्होंने कहा कि अगर हम 2023-24 में किसानों को दी गई बीमा राशि को जोड़ दें तो यह 185.259 करोड़ रुपए होगी। कलबुर्गी जिले में वर्ष 2023-24 में 1,62,071 किसानों ने 1,86,850 हेक्टेयर में उगाई गई अपनी फसलों के लिए बीमा करवाया था। संबंधित बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में 160.30 करोड़ रुपए दिए गए। प्रीमियम में किसानों का योगदान 18.47 करोड़ रुपए था, जबकि केंद्र और राज्य सरकारों ने 70.92 करोड़ रुपए का भुगतान किया।

भोपाल | जगत गांव हमार

देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने वालों की सूची में शामिल शिवराज सिंह चौहान को अब मध्य प्रदेश की सियासत से अलग हटाकर राष्ट्रीय स्तर पर गांव वालों और किसानों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलने के बाद उनकी काफी चर्चा हो रही है। वो जमीन से जुड़े नेता हैं। जनता की नब्ब को अच्छे तरीके से समझते हैं और उन्हें लोग प्यार से मामा के नाम से

पुकारते हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि शिवराज के राज में कृषि मंत्रालय के कामकाज को पटरी पर आने की उम्मीद है। ऐसी उम्मीद है कि सरकारी बाबुओं की बजाय अपने विजन से काम करके खेती-किसानी और गांवों को आगे बढ़ाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने शिवराज को यूं ही कृषि मंत्री नहीं बनाया, बल्कि उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ भी है। शिवराज ने मध्य प्रदेश में

खेती के लिए कई ऐसे काम किए हैं, जिनकी सफलताओं का सेहवा उन्हें पहचाना उचित होगा। 2005-06 से 2018-19 के दौरान मध्य प्रदेश की कृषि ज़ीडीपी 7.5 फीसदी प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है। इनमें से अतिम तीन साल और भी उल्लेखनीय रहे हैं, जब कृषि विकास दर राष्ट्रीय औसत 4.7 फीसदी की तुलना में मध्य प्रदेश में 11.5 फीसदी के रेट से बढ़ी थी। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ 27.2 फीसदी तक पहुंच गई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है।

एमपी में 'शिव' के राज में बना था एग्रीकल्चर ग्रोथ का रिकॉर्ड

किसानों की उम्मीद शिवराज

जैविक खेती का मॉडल एमपी

अगर राज्यों को जैविक खेती में आगे बढ़ाना है तो मध्य प्रदेश के मॉडल को कॉपी करना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान के शासन में उनके विजन के बंदोलत मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक फॉर्मिंग में नंबर वन बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार धरती को केमिकल वाली खेती से बचाने की अपील कर रहे हैं। ताकि धरती और इंसान दोनों की सेहत अच्छी रहे। लोगों को केमिकल फ्री खाना मिले। इस मुहिम को शिवाज राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में ऐसा करके दिखाया है। फरवरी 2024 तक की रिपोर्ट के अनुसार देश में ऑर्गेनिक खेती का रकबा 64,04,113 हेक्टेयर है। इसमें मध्य प्रदेश 15,92,937 हेक्टेयर के साथ पहले नंबर पर है।



- » अब राष्ट्रीय स्तर पर खेती और गांवों को आगे बढ़ाने का जिम्मा
- » जैविक खेती में मध्यप्रदेश 15,92,937 हेक्टेयर के साथ पहले नंबर पर
- » भारत 2027-28 तक दाल और खाद्य तेल में होगा आत्मनिर्भरता
- » दलहन-तिलहन पर नए कृषि मंत्री शिवराज सिंह का फोकस

भावांतर योजना

एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच का अंतर पाटकर किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए देश में पहली बार शिवराज ने ही स्क्रीम शुरू की, जिसे हम भावांतर भरपाई योजना के नाम से जानते हैं। चौहान ने इसे 16 अक्टूबर 2017 को शुरू किया था। राज्य सरकार ने शुरूआत में आठ फसलों के लिए यह योजना शुरू की थी, बाद में इसका विस्तार किया गया। इसके हरियाणा सरकार ने भी अपने यहां लागू किया।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर शिवराज ने अपने सूबे के किसानों को राज्य की ओर से भी डायरेक्ट सपोर्ट देना शुरू किया। इसके तहत दो किस्तों में 4000 रुपए की मदद दी जाने लगी। इसकी शुरूआत उन्होंने सितंबर 2020 में की थी। इस तरह मध्य प्रदेश के किसानों को सालाना 10,000 रुपए की डायरेक्ट सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई। बाद में इसी तरह की योजना को महाराष्ट्र ने कॉपी किया। हालांकि वहां राज्य ने भी 6000 रुपए अपनी तरफ से दिए। मध्य प्रदेश की ही तर्ज पर अब राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि के साथ राज्य सरकार भी 2000 रुपए देने जा रही है। यानी वहां के किसानों को सालाना अब 8000 रुपए मिलेंगे।

चौहान के आगे चुनौतियां

देश के नए कृषि मंत्री शिवराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसान आंदोलन को सुनझाने की है। संयुक्त किसान मोर्चा-अराजनीतिक के नेतृत्व में सवा सौ दिन से खंड और खसैरी बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। जिनमें एमएसपी की लागल गारंटी का मुद्दा प्रमुख है। तीन कृषि कानूनों के खिलफ 13 महीने तक चले आंदोलन को खत्म करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद सामने आकर गलती को स्वीकार करना पड़ा था। अब देखना यह है कि इस समय एमएसपी गारंटी को लेकर चल रहे आंदोलन को शिवराज कैसे सुझाएंगे। यह चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि किसानों की नाराजगी लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ी है। उसे कई सीटें खोनी पड़ी है।

कृषि उपज दाम पर भी करना होगा काम

कृषि क्षेत्र के लिए शिवराज की कई सफलताएं हैं, लेकिन शिष्टी में उन्हें अरबी चुनौतियों से खूबक होना पड़ेगा। खासतौर पर कृषि उपज के दाम के मोर्चे पर। प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रालय को किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य दिया हुआ है, लेकिन इस रास्ते में वाणिज्य और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आते हैं। जैसे ही किसी फसल का दाम बढ़ता है तुरंत उपभोक्ता और वाणिज्य मंत्रालय उसे गिराने की जुगत में जुट जाते हैं। या तो परसपोर्ट बैल करवा देते हैं या फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने-घटाने का खेल शुरू कर देते हैं। जिससे किसानों का नुकसान होता है। उससे उज्जनी नाराजगी की वजह से चुनाव में पार्टी को नुकसान सेवना पड़ता है।

100 दिन का प्लान पहले ही बनाया

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय का पदभार संभालते ही सुपर एक्शन मोड में हैं। उन्होंने 100 दिन का प्लान पहले ही बना लिया है। अब उस दिशा में काम शुरू हो गया है। बतौर कृषि मंत्री शिवराज ने दलहन और तिलहन को प्राथमिकता में रखा है। अधिकारियों का कहना है कि शिवराज की अगुआई वाले कृषि मंत्रालय का लक्ष्य 2027-28 तक दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। साथ ही खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू करना है। उनका कहना है कि ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका भारत अभी भी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात करता है।

पंजाब को पछड़ा

आंकड़ों को देखते हैं तो गेहूं की खरीद में सबसे टॉप पर पंजाब भिस्ता है। उसका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा है तो वो मध्य प्रदेश ही है। रबी मार्केटिंग सीजन 2020-21 में पहली बार मध्य प्रदेश ने 129.42 लाख टन गेहूं की खरीद करके पंजाब को पीछे छोड़ दिया था। गेहूं खरीद की टेंली में वो पहले नंबर पर आ गया था। सेंट्रल पूल के लिए गेहूं खरीद करने के मामले में मध्य प्रदेश का भी अहम योगदान रहता है।

उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनाएं

हाल ही में शिवराज ने कृषि राज्य मंत्रियों रामनाथ लक्षुर और भगोवर चौधरी के साथ प्रमुख अधिकारियों की एक बैठक की, जिसमें अगले 100 दिनों के प्रस्तावों की समीक्षा की गई। साथ ही कृषि अर्थव्यवस्था पर कई प्रस्तावों का अध्ययन भी किया गया। अधिकारियों ने शिवराज को चल रही योजनाओं की स्थिति, आगामी खरीफ या गर्मियों में बोई जाने वाली फसल की तैयारियों, उर्दकों और बीजों की उपस्थिति के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बालों और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजनाएं भी तैयार है।

उत्पादन में आई कमी

शिवराज ने अधिकारियों से पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अपने संकल्प पत्र में कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी गारंटियों को पूरा करने के लिए समय पर एक रोडमैप तैयार करने को कहा है। पिछले साल खराब मानसून के बाद भारत में इस साल औसत से ज्यादा गर्मी के दिन दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले साल मानसून की वजह से 2023-24 में कृषि विकास 1.7 फीसदी तक गिर गया, जो साल 2018-19 के बाद सबसे कम है। अच्छी बारिश से आगामी खरीफ या गर्मियों में बोई जाने वाली फसल का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। कोमटों पर लगातार लगावे के लिए पर्याप्त खाद्य भंडार महत्वपूर्ण है।

शिवराज से ज्यादा उम्मीद

भारत जो एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके लिए कृषि सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग आधी आबादी कृषि आर पर ही निर्भर है। विशेषज्ञों ने उम्मीद जलाई है कि शिवराज ने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के सीएस के तौर पर राजनीतियों अपनाई थीं, उन्हें यह बतौर कृषि मंत्री भी जानी रखेगी। उनके नेतृत्व में राज्य में मध्य प्रदेश में औसत कृषि विकास 7 प्रतिशत रहा था जो राष्ट्रीय औसत 3.7 प्रतिशत से ज्यादा है। शिवराज को सिंचाई का विस्तार करके और एमएसपी पर सेनास देकर मध्य प्रदेश को एक प्रमुख गेहूं उत्पादक बनाने का श्रेय भी दिया जाता है।

ताकि बढ़ सके दालों का उत्पादन

शिवराज की निगरानी में कृषि मंत्रालय का मुख्य लक्ष्य वालों का उत्पादन बढ़ाना, रकबा और पैदावार दोनों बढ़ाना होगा, ताकि अगले तीन से चार वर्षों में देश आत्मनिर्भर बन जाए। दालों का उत्पादन बढ़ाने की योजना उन्हीं राजनीतियों पर निर्भर करेगी जो तिलहन के लिए अपनाई गई हैं। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सरकार जुलाई में निर्दिष्ट बजट में राष्ट्रीय तिलहन मिशन की भी घोषणा कर सकती है। यह मिशन सरसों, मूंगफली और सोयाबीन के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने पर केंद्रित होगा।

आम नहीं खास हैं मध्यप्रदेश के आम, दुनिया भर में हैं चाहने वाले

» अवीश सोमकुवर

जनसंपर्क अधिकारी, मप्र जनसंपर्क

वया इस पहली को आप एक पल में बूझ सकते हैं? यह जनजातीय समाज में बुजुर्ग अपने पोते-पोतियों से पूछते हैं। इसका सही जवाब है - आम। यह ईश्वरीय फल है। इसका स्वाद शब्दों में बता पाना मुश्किल है। भारत में करीब 1500 किस्म का आम होता है। इनमें से कुछ प्रकार बेहद लोकप्रिय हैं और आम लोगों की जवान पर चढ़े हैं। अल्फांसो, बॉम्बे ग्रीन, केसर, नीलम, तोतापरी मालदा, सिंदूरी, बादामी, हापुस, नूरजहां, कोह-ए-तूर के नाम अक्सर लोग लेते हैं। इनमें मध्यप्रदेश के आमों का जिक्र खास है।

मध्यप्रदेश के आम बहुत खास हैं। यदि कहीं कि मध्यप्रदेश में आम पर्यटन के रूप में पर्यटन की नई शाखा सामने आई है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आलीराजपुर जिले के कठुवाड़ा का नूरजहां आम खाना तो दूर इसे देखने तक लोग दूर-दूर से आते हैं। आम आने से पहले ही एक-एक फल की बुकिंग हो जाती है। एक आम का वजन 500 ग्राम से लेकर 2 किलो तक हो सकता है। बारह इंच तक लंबा हो सकता है। स्वाद लाजवाब है। आम जब इतना खास हो जाए कि इसे देखने लोग तरस जाएं तो आम पर्यटन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जनदरी में फूल आना शुरू होते हैं और फरवरी के आखिर तक पेड़ पत्तों से लद जाता है। जून के आखिर तक फलों से भर जाता है। इसका पौधा अफगानिस्तान से गुजरात होते हुए मध्य प्रदेश आया। कठुवाड़ा में ही 37 किस्में देखी जा सकती हैं। पेड़ की ऊंचाई 60 फीट तक होती है। एक पेड़ में 100 के करीब आम निकल आते हैं। इस प्रकार करीब 350 आम पांच पेड़ों से मिल जाता है। एक आम 500 रूपए से लेकर 2000 तक बिक जाता है।

रीवा का सुंदरजा: पिछले साल रीवा के गोविंदगढ़ में होने वाले सुंदरजा आम को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने खुश होकर ट्वीट साझा किया था। वर्ष 1968 में सुंदरजा पर डाक टिकट जारी हो चुका है। सुंदरजा आम देखने में जितना सुंदर है स्वाद में उतना ही लाजवाब है। इसकी सुगंध मदहोश करने वाली है। बारिश की पहली फुहार के बाद यह पकता है। गोविंदगढ़ के वातावरण में ही यह पनपता है क्योंकि यहाँ मिट्टी और तापमान दोनों का विशेष महत्व है सुंदरजा पेड़ को फलने-फूलने के लिए। इसकी पत्तियां, छाल गुठलियां सब काम आती हैं। यह एंटीऑक्सिडेंट है। विटामिन-ए, विटामिन-सी और आयर्न से भरपूर है। शक्कर की मात्रा कम होती है इसलिए मधुमेह के मरीज भी इसे पसंद करते हैं। सुंदरजा रीवा जिले और पूरे मध्य प्रदेश की भी पहचान बन गया है। एक जिला एक उत्पादक परियोजना में सुंदरजा को शामिल किया गया है। रीवा के फल अनुसंधान केंद्र कठुवाड़ा में आम पर आगे रिसर्च लागाने चल रही है। यहाँ विभिन्न किस्मों के आम के 2345 पेड़ हैं। इनमें बॉम्बे ग्रीन, इंदिरा, दशहरा, लंगड़ा, गधुवा, आग्रपाली, मलिका मुख्य हैं।

बाणसागर की नहर के कारण इस क्षेत्र में खेती विकसित हो गई है। साथ ही उद्यमिकी फसलों की पैदावार भी बढ़ी है। इसी के साथ खाद्य प्रसंस्करण लघु उद्योगों की भी भरपूर संभावनाएं बनी हैं। गोविंदगढ़ क्षेत्र में ही आम के कई बाग हैं। यहाँ करीब 237 किस्म के आम मिल जाते हैं। सभी स्वाद में एक दूसरे से बढ़कर हैं। यहाँ से फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड और अरब देशों को आम निर्यात होता है।



जबलपुर का मियाजाकी: जबलपुर में सबसे महंगे आम मियाजाकी के दुनिया में भूम मचा दी है। एक आम की कीमत 20000 रूपये तक पहुंच जाती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तीन लाख रूपये किलो तक कीमत मिल जाती है। यह लाल रंग का होता है। एक आम 900 ग्राम से लेकर डेढ़ किलो तक का होता है। यह जापान की किस्म है जो थाईलैंड, फिलिपींस में भी होती है। जापान में इसे सूयूज का अंडा कहते हैं। जबलपुर में 1984 से इसका उत्पादन हो रहा है। इसे पकाने के लिए गमक

मौसम और बारिश दोनों की जरूरत होती है। जबलपुर से सटे डगडागा हिनौता गांव में इन आमों को दूर से देखा जा सकता है। यहाँ आम के पेड़ कड़ी सुखा में रहते हैं। इसके मालिकों की सारी ऊर्जा पेड़ों की सुखा में लग जाती है। मध्यप्रदेश से अब बांग्लादेश अरब, यूके, कुवैत, ओमान और बहरीन देशों को आम का निर्यात हो रहा है।

आम का इतिहास: आम फल का इतिहास करीब 5000 सालों का है। यह इंडो वर्मा रीजन में पैदा हुआ और पूर्वी भारत और दक्षिण चीन तक पूरे साइबेरिया में विस्तार से मिलता था। वर्ष 1498 में जब पुर्तगाली कोलकाता में उतरे तो उन्होंने आम का व्यापार स्थापित किया। आम ट्रापिकल और सब ट्रापिकल जलवायु में अच्छा फलता है। प्राथमिक रूप से यह ब्राजील, इकाडोर, ग्वाटेमाला, हैती, मेक्सिको, पेरू में भी पाया जाता है। आम का इतिहास बताता है की अंग्रेजी का मंगो शब्द मलयालम के 'मंगा' और तमिल के 'मंगार्ड' से बना है। आम की टहनियों को जोड़कर तरह-तरह की नई किस्में पैदा करने की कला पुर्तगालियों की देन है। जैसे अल्फांसो का नाम एक सैन्य विशेषज्ञ अल्बुकर्क के नाम पर रखा गया। भारत आए चीनी यात्री व्हेन सांग ने दुनिया को बताया कि भारत देश में आम का फल होता है। मौर्य काल में आम के पेड़ रोड के किनारे लगाए जाते थे जिन्हें समृद्धि का प्रतीक माना जाता था।

आम का पेड़ 60 फीट तक ऊंचा हो सकता है और 4 से 6 साल में ही आम देने लगता है। आम का पेड़ पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है और इसका उपयोग अपने तने, शाखाओं के लिए करता है। इसलिए आम की पत्तियों को शादियों के मंडपों, घरों में तोरण के रूप में लगाई जाती हैं।

मप्र में आम का उत्पादन

मध्यप्रदेश में पिछले 8 सालों के आम उत्पादन, क्षेत्र और उत्पादकता के आंकड़ों का अध्ययन करने से पता लगता है कि आम फल का उत्पादन और क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2016-17 में उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 13.03 मीट्रिक टन थी जो 2023-24 में बढ़कर 14.66 हो गई है। इसी प्रकार 2016-17 में आम का क्षेत्र 43609 हेक्टेयर था जो 2023-24 में बढ़कर 64216 हो गया है। इसी दौरान उत्पादन 5,04,895 मीट्रिक टन था जो अब बढ़कर 9,41, 352 मीट्रिक टन हो गया है।

बढ़ती गर्मी से दुधारू पशुओं में बढ़े हीट स्ट्रोक के मामले

» डॉ. आनंद फिरार, » डा. निर्मला मुखेल, » डॉ. सुनील नायक, » अंकुर खरे, » डॉ. राहुल खर्वा, » डॉ. प्रद्युम्न सिंह, » डॉ. अंकित पचौरी, » डॉ. लौरभ नागवैशी, » डॉ. पंकज बर्ड, » डॉ. श्रेयाश मिश्रा

पशु पोषण विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय जबलपुर

आसमान से बरसते शोलों के बीच हिंदुस्तान के तमाम जिलों का तापमान लगातार सुरसा के मुंह के समान बढ़ता जा रहा है। आम जन-जीवन गर्मी और गरम हवाओं के चलते बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ऐसे में पशुओं की जिन्दगी पर भी बुरा असर अब पड़ने लगा है। हिंदुस्तान के प्रमुख राज्यों में पशु सम्बंधन एवम संरक्षण पर विशेष जोर है, ऐसे में भीषण गमीज से डेरी पशुओं में गर्मी से अत्यधिक खतरा है और इस गर्मी से इन पशुओं पर अनेक हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं, इसे लू कहा जाता है।

जब शरीर सामान्य ठंडक नियंत्रण में असमर्थ हो जाता है तब शरीर का तापमान सामान्य से बढ़ जाता है, जिसे हम हीट स्ट्रोक/ लू कहते हैं। मनुष्यों के विपरीत, कई जानवर पसीने के माध्यम से अपने शरीर के तापमान को दुशालतापूर्वक नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हीट स्ट्रोक आमतौर पर तब होता है जब शरीर में पानी और नमक की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है अथवा पसीना आना भी कम या बंद हो जाता है।

हीट स्ट्रोक के प्रमुख कारण क्या है?

वैसे तो हीट स्ट्रोक के कई कारण हो सकते हैं परन्तु इनमें मुख्य रूप से गर्म हवाओं का चलना, कम आकार के पशु शाला में ज़रूरत से ज्यादा पशुओं को रखना, स्वच्छ हवा की कमी और पशुओं के शरीर में पानी तथा नमक की कमी होना सम्मिलित है।

हीट स्ट्रोक के प्रमुख लक्षण क्या है?

प्रमुख लक्षणों के अंतर्गत पशुओं के शरीर का तापमान सामान्य से बढ़ जाता है। चाल सुस्त होने के साथ खाना पीना कम या छोड़ देता है। जीभ बाहर निकाल कर कटिनाई से सांस लेता है। मुंह व नाक से झाग आने से आँख और नाक लाल हो जाते हैं। हृदय गति बढ़ने से पशु चक्कर खाकर बेहोश होने लगता है। सही समय पर इस बीमारी का इलाज नहीं किया जाए तो पशु की असाध्यिक मौत हो सकती है।

हीट स्ट्रोक की वजह से खान पान में कमी की वजह से दुग्ध उत्पादन में 10 से 25 प्रतिशत की गिरावट, दूध में वसा के प्रतिशत में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी एवं प्रतिरक्षा प्रणाली में कमी इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं।

गर्मियों में पशु की देखभाल कैसे करें?
दूधारू पशुओं के आहार में हरे चारे की मात्रा बढ़ा दें, बता दें कि हरे चारे में पानी की अच्छी मात्रा होती है जिससे पशुओं की पानी की कमी पूरी हो जाती है। परन्तु गर्मियों कि समय में हरे चारे का उत्पादन काफी कम हो जाता है, ऐसे में चाहिए की पशु पालक के द्वारा पशु अचार एवं

पेरिनिअल चारे का उत्पादन एवं उपयोग करा जाए।

पशुओं को दिन में 3-4 बार स्वच्छ पानी पिलाया जाए। पशुओं को पानी में पचास मात्रा में नमक और आटा मिलाकर पिलाए।

पशुओं को गरम हवाओं से बचाकर रखें।

पशुओं के रहने के स्थान की छत पर सूखी घास, पुआल आदि बिछाए।

पशुओं को रोजाना ठंडे पानी से नहलाए।

हीट स्ट्रोक का इलाज किस प्रकार करें?

(पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार एवं परिस्थिति अनुसार)

हीट स्ट्रोक होने पर पशु के शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है जिसके नियंत्रण के लिए पशुपालक द्वारा ठंडे पानी से सिकाई करना चाहिए।

आवश्यकता अनुसार पशु का ड्रिप अथवा इंजेक्शन से ग्लूकोस देना चाहिए।

खुआर अथवा शरीर के तापमान को कम करने के लिए तापमान नियंत्रक (एंटी-पायरेटिक) इंजेक्शन या दवा दें।

आवश्यकता अनुसार एंटी बायोटिक दवा का उपयोग कर सकते हैं।

साथ ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एवं विटामिन सी देने से पशु संक्रमित बीमारियों के

खतरे से बाहर रहते हैं।

पशुओं के खाने में प्रमुख रूप से विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे की आंवला एवं अंकुरित अनाज सम्मिलित करें जिससे की पशु तनाव मुक्त एवं उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले हो पाएँ।

गर्मियों के समय में प्रमुख रूप से पशुओं के खाने में वसा युक्त खाद्य पदार्थ सम्मिलित करें जैसे की पशु वसा, वनस्पति तेल, मिश्रित वसा और उप-उत्पाद तेल। हीट स्ट्रोक के कारण विटामिन डी का परिवर्तन मेटाबोलिक एक्टिव फार्म 1,25 (ओएफ)2 डी-3 में नहीं हो पाता, जो की कैल्शियम की अवशोषण एवम उपयोग के लिए आवश्यक है कैल्शियम का सेवन बढ़ाना उचित है।

40 सालों में 40 फीसदी बढ़ा नाइट्रस ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि साल 1980 से 2020 के बीच धरती की गर्म करने वाली नाइट्रस ऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में 40 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से ज्यादा शक्तिशाली गैस के बड़े पांच उत्सर्जन करने वालों में चीन (16.7 फीसदी), भारत (10.9 फीसदी), अमेरिका (5.7 फीसदी), ब्राजील (5.3 फीसदी) और रूस (4.6 फीसदी) थे।

प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की बात करें तो यह अलग-अलग होता है। जबकि भारत में प्रति व्यक्ति नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन सबसे कम 0.8 किग्रा. है, अन्य शीर्ष प्रति व्यक्ति उत्सर्जकों में चीन 1.3, अमेरिका 1.7, ब्राजील 2.5 और रूस 3.3 किग्रा. है।

जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा नामक पत्रिका में प्रकशित अध्ययन में कहा गया है कि वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड का उच्च स्तर ओजोन परत को नष्ट कर सकता है और जलवायु में बदलाव के प्रभावों को बढ़ा सकता है। पृथ्वी पर अतिरिक्त नाइट्रोजन मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी करता है।

अध्ययन में कृषि उत्पादन और पशुपालन नाइट्रस ऑक्साइड के दो प्रमुख मानवजनित स्रोत पाए गए। अध्ययन के अनुसार, पिछले दशक में कृषि उत्पादन, मुख्य रूप से नाइट्रोजन उर्वरकों और पशु खाद के उपयोग के कारण, कुल मानवजनित नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में 74 फीसदी की बढ़ोतरी करता है।

अध्ययन के मुताबिक, 1980 में दुनिया भर के किसानों ने छह करोड़ मीट्रिक टन व्यावसायिक नाइट्रोजन उर्वरकों का इस्तेमाल किया था। 2020 तक, इस क्षेत्र ने 10.7 करोड़ मीट्रिक टन का इस्तेमाल किया। अध्ययन के अनुसार, उसी वर्ष, पशु खाद ने 10.1 करोड़ मीट्रिक टन का योगदान दिया, जो 2020 में कुल 20.8 करोड़ मीट्रिक टन पहुंच गया। अध्ययन में शामिल 18 क्षेत्रों में से केवल यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, तथा जापान और कोरिया में नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। 1980 से 2020 के बीच यूरोप में कमी की दर सबसे अधिक थी, जिसका कारण जीवाश्म ईंधन और उद्योग उत्सर्जन में कमी थी। दूसरी ओर, चीन और दक्षिण एशिया में 1980 से 2020 के बीच नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे अधिक 92 प्रतिशत की वृद्धि हुई। शोधकर्ता ने अध्ययन के हवाले से कहा कि पेरिस समझौते के अनुसार, वैश्विक तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए मानवजनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आनी चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना ही एकमात्र समाधान है क्योंकि इस समय ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है जो वायुमंडल से नाइट्रस ऑक्साइड को हटा सके।

नाइट्रस ऑक्साइड महासागरों, जल निकायों और मिट्टी जैसे प्राकृतिक स्रोतों से भी उत्सर्जित होता है। इन स्रोतों ने 2010 से 2019 के बीच गैस के वैश्विक उत्सर्जन में 11.8 प्रतिशत का योगदान दिया।

-मोहन कैबिनेट: 24 हजार 420 करोड़ की सब्सिडी मंजूरी

मप्र में किसानों के लिए सरकार ने खोला खजाना

भोपाल | जगत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक में कृषि उपभोक्ताओं को 13,000 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। इसी तरह घरेलू उपभोक्ताओं को 5000 करोड़ और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को भी 5000 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दी जाएगी। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा भर्ती नियम 2022 में प्रावधानित विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत 12,214 पदों में से 50 प्रतिशत यानी 607 पदोन्नति के पदों की पूर्ति भी सीधे भर्ती के माध्यम से की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति की अनुशंसा के आधार पर स्वास्थ्य संस्थानों में स्वीकृत एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए 40491 नए नियमित, संविदा और आउटसोर्सिंग के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इनमें से 18,653 पदों की पूर्ति आगामी तीन वर्ष में की जाएगी। इस पर वार्षिक 343 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। शेष 27,828 पदों की पूर्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से की जाएगी।

नए विवि को तीन करोड़

कैबिनेट बैठक में रानी अवंती बाई लोधी विश्वविद्यालय सागर, क्रांति सूर्यकांत टंट्या विवि खरगोन तथा क्रांतिवीर तात्याटोपे विवि गुना में से प्रत्येक नए विवि की प्रारंभिक आवश्यकता के लिए तीन करोड़ की स्वीकृति दी गई। साथ ही प्रति वर्ष ब्लॉक ग्रांट भी दी जाएगी।



भोपाल गैस त्रासदी: प्रतिनियुक्ति या संविदा नियुक्ति का निर्णय

मंत्रि-परिषद ने भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति अथवा विभाग के अधीन प्रशासित संविदा भर्ती नियम 2003 के अंतर्गत संविदा पर लिए जाने का निर्णय लिया गया। संविदा पर भरे जाने की स्थिति में वरिष्ठ परामर्शी (चिकित्सा महाविद्यालय के प्राध्यापक के समकक्ष), परामर्शी (चिकित्सा महाविद्यालय के सह प्राध्यापक के समकक्ष), कनिष्ठ परामर्शी/विशेषज्ञ (चिकित्सा महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक के समकक्ष) और चिकित्सा अधिकारी को समेकित पुनरीक्षित पारिश्रमिक (रुपए) पर नियुक्ति दी जाएगी।

गौवंश रक्षा वर्ष मनाने का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने गौवंश की रक्षा करने के संकल्प के साथ इस वर्ष की चैत्र की गुड़ी पड़वा से अगले वर्ष तक गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने का अनुमोदन दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में यह निर्णय लिया गया था, जिसका मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन दिया। मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन द्वारा यह साल, गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जो प्रतिपदा, चैत्र, शुक्ल पक्ष 9 अप्रैल 2024 से आगामी अमावस्या, चैत्र, कृष्ण पक्ष, 29 मार्च 2025 तक मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड के अंतर्गत मनाया जा रहा है। प्रदेश में संचालित गौ-शालाओं को श्रेष्ठ संचालन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। सड़कों पर गाय दुर्घटना का शिकार होती है। ऐसी व्यवस्था होगी कि घायल गाय को इलाज के लिए आसानी से ले जाया जा सके।

- » प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में होगी 40 हजार नई भर्तियां
- » कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगे 13,000 करोड़ अनुदान
- » घरेलू उपभोक्ताओं को 5000 करोड़ दी जाएगी सब्सिडी
- » अजाज वर्ग के अन्नदाताओं को भी 5000 करोड़ की छूट
- » तीन नए विवि की स्थापना, शहडोल विवि के लिए वित्तीय सहायता

10 करोड़ का प्रावधान

पहले वित्तीय वर्ष के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही नवीन विश्वविद्यालयों के लिए 235 पदों की स्वीकृति भी दी गई। भवन निर्माण के लिए डेढ़ सौ करोड़ प्रत्येक विवि तथा पंडित शंभूनाथ शुक्ल विवि शहडोल के लिए 45 करोड़ की स्वीकृति भी गई।

किसान तुरंत करा लें रजिस्ट्रेशन, सीधे बैंक में आएगा पैसा

अरहर और मूंग दाल की बोवनी के लिए किसानों को प्रेरित किया

अरहर दाल की एमएसपी पर 100% खरीद करेगी सरकार



भोपाल | जगत गांव हमार

केंद्र सरकार दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए किसानों को दालों की बुवाई के प्रेरित कर रही है। इसके लिए बैंक पर किसानों को कम कीमत पर दालों के बीज, उर्वरक और कीटनाशक समेत कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। अब केंद्र ने कहा है कि दालों की उपज की सरकारी खरीद 25 फीसदी नहीं बल्कि पूरी 100 फीसदी की जाएगी। किसानों से ऑनलाइन पोर्टल पर बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है। सरकार किसानों से दाल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर करेगी। दाल उत्पादन में बढ़ोत्तरी के साथ ही सरकारी खरीद ज्यादा करने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। बुवाई रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत देश भर में 150 से अधिक बीज केंद्र

स्थापित कर रखें हैं। जबकि, ऑनलाइन भी बीजों, उर्वरकों की उपलब्धता आसान की जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दालों का उत्पादन 2014 में 171 लाख टन था, जो 60 प्रतिशत बढ़कर 2024 में 270 लाख टन हो गया है। खपत अधिक होने के चलते दालों का आयात अभी भी करना पड़ रहा है।

आत्मनिर्भर बनने का टारगेट - केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि अगले 3 वर्षों में दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2027 तक अरहर यानी तूर दाल के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। केंद्र के अनुसार किसानों से अरहर दाल की सरकारी खरीद 25 फीसदी नहीं होगी, बल्कि 100 फीसदी खरीद की जाएगी। केंद्र ने खरीफ सीजन के लिए अरहर और मूंग दाल की बोवनी के लिए किसानों को प्रेरित किया है।

400 रुपये बढ़कर मिलेगा अरहर का एमएसपी रेट

ताजा निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार का है वादा कि प्रत्येक अरहर किसान को मिलेगा शत-प्रतिशत खरीदारी की गारंटी दी जा रही है। केंद्र किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अरहर दाल की खरीद करेगी। अरहर दाल पर एमएसपी रेट 2023-24 में 400 रुपये बढ़कर 700 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। 2022-23 सीजन के लिए एमएसपी रेट 6600 रुपये प्रति क्विंटल था और 2021-22 सीजन के लिए 6300 रुपये एमएसपी रेट था।

सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं किसान

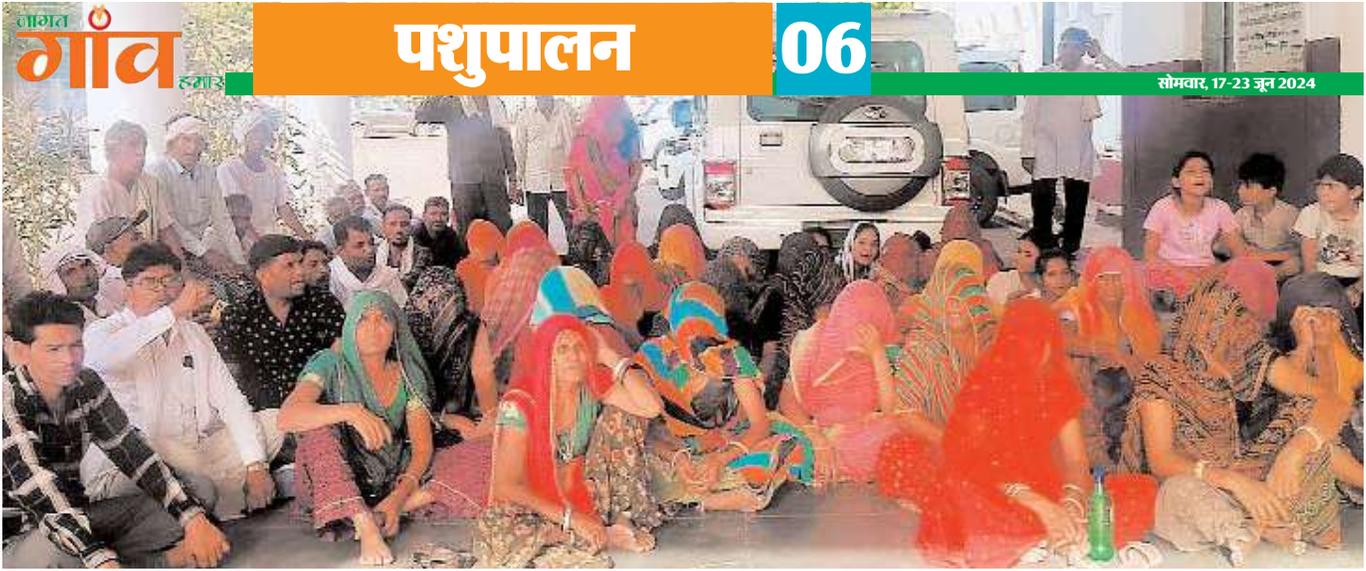
सरकार ने अरहर किसानों से कहा है कि वह अपनी उपज को एमएसपी दर पर बेचने के लिए ई-समृद्धि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लें। किसानों की अरहर उपज की खरीद दो सहकारी समितियों नेफेड और एनसीसीएफ करेगी और ये किसानों की फसल का भुगतान सीधे उनके बैंक अकाउंट में करेगी। ई-समृद्धि पोर्टल पर अरहर दाल ही नहीं बल्कि, मक्का समेत कई दूसरी फसलों की भी बिक्री कर सकते हैं। पोर्टल पर अब तक 1.37 करोड़ किसान रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं।

राज्यपाल ने की पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की समीक्षा

जरूरतमंदों को मिले दुधारू पशु प्रदाय योजना का लाभ



भोपाल। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना का लाभ गरीब और जरूरतमंदों को मिले। हितग्राहियों के चिन्हांकन में उनकी आर्थिक स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाए। पशुपालकों को पशु प्रदान करते समय अच्छे नस्ल के स्वस्थ पशु प्रदान करें। उन्हें पशुओं के रख-रखाव आदि की जानकारी दे। राज्यपाल ने उक्त निर्देश राजभवन में आयोजित पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। राज्यपाल ने कहा कि दुधारू पशु प्रदाय योजना के अंतर्गत पशुपालकों के लिए दुग्ध संग्रहण की विशेष व्यवस्था बनाए। पटेल ने दुधारू पशु प्रदाय योजना के तहत प्राप्त लक्ष्य तथा उपलब्धि, बजट एवं आगामी प्रस्तावों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि योजना के लक्ष्य को संबोधित वरिष्ठ आवश्यकतानुसार बढ़ाएं और उसे प्राप्त करने का भरसक प्रयास करें। राज्यपाल श्री पटेल ने बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति क्षेत्रों में पशुप्रदाय योजना की विगत और वर्तमान स्थिति की तुलनात्मक समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान प्रदान करते समय अच्छे नस्ल के स्वस्थ पशु प्रदान करने के लिए पात्रता निर्धारण, पशु चयन और वितरण की समस्त प्रक्रिया को विस्तार से जानकारी ली। राजभवन के जवाहर खण्ड में आयोजित बैठक में जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खण्डेकर, राज्यपाल के प्रमुख सचिव मुकेश चन्द गुप्ता, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बागरा, राज्यपाल के अपर सचिव उमाकांत भार्गव, राज्यपाल के विधि अधिकारी उमेश श्रीवास्तव, संचालक पशु पालन एवं डेयरी विकास और संबन्धित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।



सूंडी गांव से विस्थापितों बसाने के लिए जिला प्रशासन को नहीं मिल रही सरकारी भूमि

विहलपुर से आए एक सैकड़ किसानों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

विस्थापितों को बसाने में फिर रार विहलपुर के किसानों ने किया विरोध

स्थोपाट। जागत गांव हमारे

पार्वती नदी के बीच बसे सूंडी गांव को विस्थापित कराने के लिए प्रशासन को सरकारी जमीन ही नहीं मिल रही है, जिसके चलते कई सालों से इस गांव को विस्थापित करने और बसाने की योजना बन-बिगड़ रही है। अब प्रशासन ने सूंडी को विहलपुर और जवाड़ गांव में बसाने की प्लानिंग तैयार कर डाली जिसके विरोध में विहलपुर गांव के किसान लामबंद हो गए हैं। इसी क्रम में बीते सप्ताह ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंप सूंडी गांव के किसानों को अपने यहां बसाने का विरोध कर डाला।

विहलपुर के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि साहब-हम बाप दादाओं के जमाने से ही विहलपुर गांव में बसे हुए हैं। इसी आधार पर सरकार ने हमें 50 साल पहले विहलपुर

और जवाड़ गांव में खेती बाड़ी करने के लिए जमीनों के पट्टे दिए थे जहां पर हम खेती-बाड़ी करके आजीविका चला रहे हैं पर अब चोरी छुपे

सरकार हमारे गांव में सूंडी से विस्थापितों को उस जमीन पर बसाना चाहती है जहां हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम बर्बाद हो

सूंडी में हर साल चलाना पड़ता है रेस्क्यू

ग्राम पंचायत अडवाड़ के अंतर्गत आने वाला सूंडी गांव पार्वती नदी के बीच बने टापू पर बसा है। इस गांव में रहने वाले लोग पार्वती नदी से थिरे हुए हैं। बारिश के समय यह गांव टापू बन जाता है। गांव के डूब जाने की स्थिति निर्मित हो जाती है जिसके कारण शासन प्रशासन को इस टापू पर बसे ग्रामीणों को बचाने के लिए रेस्क्यू चलाना पड़ता है। बार बार निर्मित होने वाली ऐसी स्थिति से बचाने के उद्देश्य सरकार ग्रामीणों को दूसरे स्थान पर बसाने की योजना बना रही है। पहले वन विभाग की 100 बीघा जमीन ग्रामीणों को बसाने के लिए चिह्नित की गई थी, लेकिन वन विभाग ने शासन की मंजूरी के बाद भी अडंगा लगा दिया जिससे प्रस्ताव अटक गया एक दो स्थानों पर और जगह तलाशी गई, लेकिन बात नहीं बनी। अब जवाड़ गांव में जमीनों को तलाशा गया है जिसमें बड़ी संख्या में वो किसान प्रभावित हो रहे हैं जो बाप दादाओं की जमाने से वहां खेती-बाड़ी करते आ रहे हैं।

जाएंगे। ज्ञापन सौंपने से पहले ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे तक कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। ग्रामीणों ने बताया कि तत्कालीन प्रशासन सूंडी गांव को विस्थापित करने के लिए विहलपुर जवाड़ गांव में बसाने के लिए झूठी रिपोर्ट लगाई है। अगर यहां पर सूंडी गांव के विस्थापितों को बसाया गया तो फिर विहलपुर जवाड़ के किसानों को अन्य गांव में ले जाकर बसाना पड़ेगा। इस दौरान किसान नेता राधेश्याम मुंडला भी किसानों के साथ धरने पर बैठे थे, जिन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि अगर प्रशासन उनकी मांगी नहीं मानता है और उनके साथ ज्यादती होती है तो वह किसानों के आंदोलन को प्रदेश व्यापी आंदोलन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

पौध रोपण के लिए चिन्हित की 1690 हेक्टेयर वन भूमि हो रही तैयार

वन विभाग हरियाली बढ़ाने के लिए रोपेगा दस लाख पौधे

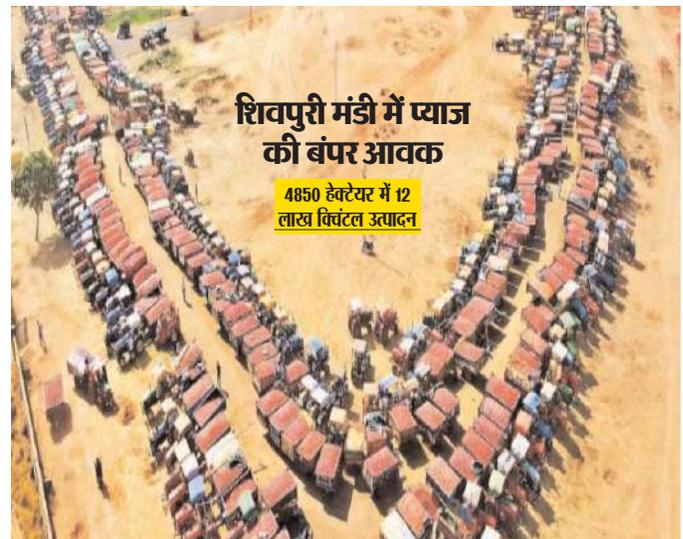


स्थोपाट। जागत गांव हमारे

जिले में हरियाली बढ़ाने के लिए वन विभाग 1690 हेक्टेयर वन भूमि पर 10 लाख से ज्यादा पौधों का रोपण करेगा। पौध रोपण के लिए 38 स्थान निर्धारित कर लिए गए हैं। वहीं अन्य तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बारिश होने के साथही वन विभाग इन पौधों का रोपण शुरू कर देगा। विशेष बात यह है कि पौध रोपण के दौरान ऐसे औषधीय पौधों के रोपण पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिनका उपयोग कई तरह

की औषधियां बनाने के लिए किया जाता है। बता दें कि जिले के जंगल में ऐसी औषधीय युक्त पौधे भी पाए जाते हैं, जिनका उपयोग कई प्रकार की आयुर्वेदिक दवाओं के बनाने में होता है। डीएफओ सीएस चौहान के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 38 स्थानों पर 1690 हेक्टेयर भूमि पर प्लांटेशन विकसित किया जाएगा। जहां 10 लाख 50 हजार 750 पौधों का रोपण किया जाएगा। डीएफओ चौहान ने बताया कि पौध रोपण के लिए जो वन भूमि चिन्हित की गई है, वहां पर सागौन, आवला, खैर, खमैर, चिरोल, शोस्सु, बरगद, पीपल, बैलपत्र, अर्जुन, तथा सलई आदि प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाएगा। इनमें से कुछ प्रजातियां तो ऐसी हैं, जिनका उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।

चयनित स्थानों पर वन विभाग पौधों का रोपण संबंधित वन समितियों के माध्यम से करेगा। इस दौरान वन समितियों से जुड़े लोगों की न सिर्फ सहभागिता बढ़ाई जाएगी, बल्कि वे कौन-कौन से औषधीय पौधों का रोपण अपने-अपने क्षेत्र के प्लांटेशन करवाना चाहते हैं, इस बारे में उनकी सहमति ली जाएगी। पौध रोपण के लिए क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार भी उपलब्ध होगा, क्योंकि उन्हें वन विभाग पौध रोपण की मजदूरी उपलब्ध कराएगा।



शिवपुरी मंडी में प्याज की बंपर आवक

4850 हेक्टेयर में 12 लाख क्विंटल उत्पादन

शिवपुरी। जिले में पिछले एक दशक से प्याज की बंपर पैदावार हो रही है। अन्य फसलों की तुलना में प्याज से अधिक मुनाफा होने के कारण किसानों में प्याज के प्रति रुचि बढ़ रही है। उद्यानिकी विभाग के अनुसार इस वर्ष किसानों ने 4850 हेक्टेयर में प्याज का उत्पादन किया है। इस वर्ष 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 12 लाख क्विंटल से अधिक प्याज का उत्पादन होने का अनुमान है। खास बात यह है कि शिवपुरी के अलावा गुना, अशोकनगर सहित पड़ोसी राज्य राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से भी किसान शिवपुरी मंडी में प्याज बेचने आ रहे हैं। शिवपुरी मंडी में मार्च 2024 से आवक शुरू हो गई थी। करीब दो सप्ताह तक प्याज का रस रहेगा। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार किसानों को प्याज के बेहतर दाम मिलें हैं। बंपर उत्पादन के कारण कृषि उपज मंडी शिवपुरी की आय में इजाफा हुआ है।

उत्तर प्रदेश से 4 से 5 गाड़ी आलू की आवक

लहसुन की आवक दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। अधिकांश किसानों ने अपना माल पहले ही स्टॉक कर दिया है। अब आलू के अधिकांश सैदे कोल्ड स्टोरेज के जरूर ही हो रहे हैं। दक्षिण और महाराष्ट्र में आलू की खेती शुरू हो गई है। ऐसे में दो से ढाई महीने में क्या माल आना शुरू हो गया है। रूढ़ी से केराब चार से पांच गाड़ी मंडी पहुंच रही हैं। सब्जों में स्थानीय आलू की होने की उम्मीद है। मंडी में 70 हजार प्याज, 10 हजार आलू और 10 हजार यूनिट लहसुन बिक चुका है।



पॉलिथीन के अत्याधिक प्रचलन ने सुरम्य नदी को नाले में तब्दील करने का काम किया

ले डूबी अनदेखी

हर साल जल संरक्षण अभियान के नाम पर करोड़ों का भेजा जाता है फंड, फिर भी नतीजा सिफर

श्योपुर के लिए जीवनदायिनी माने जाने वाली सीप के प्रति गंभीर नहीं शहरवासी

श्योपुर। जगत गांव हमार
जीवनदायिनी माने जाने वाली सीप नदी उपेक्षा के चलते सुंदर सुरम्य नदी से गंदे नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है। सीप का अस्तित्व समाप्त करने में सबसे अधिक योगदान पॉलिथीन के अत्याधिक प्रचलन से हुआ है।
कराहल के पनवाड़ा से शुरू हुआ सीप का सफर श्योपुर होते हुए मानपुर के आगे रामेश्वर धाम में चंबल बनास नदी के साथ त्रिवेणी संगम के रूप में विसर्जित होने के साथ संपन्न होता है। सीप का सफर दो भागों में बटा हुआ है। पहला पनवाड़ा से श्योपुर शहर बंजारा डैम तक और दूसरा श्योपुर बंजारा डैम से साईकला, मेवाडा, मानपुर होते हुए रामेश्वर त्रिवेणी संगम तक। बंजारा डैम तक तो स्टॉप डेम बना होने के कारण सीप नदी में कम्पोजेबल पूरे साल पानी भरा रहता है लेकिन, बंजारा डैम से नीचे सीप

का जलस्तर हमेशा सूखा ही रहता है। हालकी गर्मियों में ऊपरी हिस्से में भी सीप सूख जाती है, जैसा कि अभी हो रहा है। पानी का जलस्तर कम होने से सीप का स्वरूप गंदे नाले की तरह दिखाई देने लगा है। सीप के अस्तित्व को बचाने का एकमात्र उपाय जगह-जगह स्टॉप डेम बनाकर किया जा सकता है। इसके लिए सरकार के पास फंड की भी कमी नहीं है क्योंकि, हर साल जल संरक्षण अभियान के नाम पर करोड़ों रुपए का फंड भेजा जाता है लेकिन, इस फंड को खर्च करने की औपचारिकता अर्थ लाभ के लिए की जाती रही है। इस वजह से सीप का अस्तित्व खतरे में है। जानकारों की माने तो अगर जल संरक्षण का पैसा सीप नदी पर जगह-जगह स्टॉप डेम बनाकर खर्च किया जाए तो इसका अस्तित्व सुधरेगा और क्षेत्र में पानी की समस्या की कमी भी दूर हो जाएगी।



पॉलिथीन लील रही सीप का अस्तित्व

नदी को सबसे अधिक नुकसान पॉलिथीन से हो रहा है। दरअसल, शहर वासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाली पॉलिथीन सड़क पर फेंक दी जाती है जो नालियों से नालों में होते हुए नदी में प्रवाहित हो रही है। पॉलिथीन नदी के पानी को उथला और कीचड़ युक्त कर रही है। हालांकि भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक अभियान चलाया हुआ है जिसके तहत पॉलिथीन का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है लेकिन नगर पालिका परिषद या प्रशासन इस अभियान को सफल बनाने के प्रति कभी गंभीर ही दिखाई नहीं दिया। यही कारण है कि आज वर्षा काल पूर्व जो नालों की सफाई कराई जा रही है उनमें कचरे के रूप में सबसे अधिक पॉलिथीन ही बाहर निकल रही है जो नालों को चौक कर सड़कों पर गंदा पानी भरने का काम कर रही है। यही पॉलिथीन नालों के माध्यम से नदी में प्रवाहित हो रही है।

अमल में नहीं आ सकी सीप को निर्मल बनाने की योजना

पॉलिथीन को नदी में जाने से रोकने के लिए 10 साल पहले नालों में जाल लगाकर पॉलिथीन विभक्ति कारण योजना बनाई थी लेकिन आज वह जाल कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उधर, हाल ही में अमृत 0.2 योजना के तहत नगर पालिका ने नाला कॉरिडोर योजना बनाकर नालों के पानी को शुद्ध करने के बाद सीप में प्रवाहित करने की योजना बनाई तो है लेकिन यह योजना फाइलों से बाहर नहीं निकल पा रही है।

सामान्य मानसून की संभावनाओं के बीच कृषि विभाग ने तय किया खरीफ फसलों का लक्ष्य

एकलाख 55 हजार हेक्टेयर में होगी खरीफ फसल की बोवनी

श्योपुर। जगत गांव हमार
इस बार अच्छे मानसून की उम्मीद को लेकर जिले के किसानों ने खरीफ सीजन की फसलों की बोवनी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं कृषि विभाग ने भी खरीफ का रकबा तय कर लिया है। हालांकि अभी मानसून आने में समय है लेकिन कृषि विभाग ने खरीफ फसलों की बोवनी की तैयारियां आरंभ कर दी हैं। इस बार लगभग एक लाख 55 हजार 200 हेक्टेयर में खरीफ की बोवनी का लक्ष्य निर्धारित किया है। कृषि विभाग ने वर्ष 2024 के खरीफ सीजन के लिए तिलहन, दलहन और मोटे अनाजों की बोवनी का जो लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है, उसके मुताबिक इस बार 1 लाख 55 हजार 200 हेक्टेयर में बोवनी होगी। गत वर्ष की बोवनी को



देखते हुए इस बार थोड़ा रकबा बढ़ाया गया है। यूं तो खरीफ सीजन में दर्जन भर से अधिक फसलें बोई जाती हैं, लेकिन किसानों का मुख्य फोकस धान, बाजरा, उड़द आदि फसलों पर ही रहता है। किसानों का अब सोयाबीन की फसल से मोहभंग सा हो गया है। जिसकारण सोयाबीन की फसल का रकबा साल दर साल घटता जा रहा है।

धान का रकबा 45 हजार हेक्टेयर तय: कभी जिले में सोयाबीन की बोवनी 30 हजार से ज्यादा हेक्टेयर में होती थी, लेकिन अब सोयाबीन का रकबा 30 हजार पर आ गया है। लेकिन धान के प्रति किसानों की रूचि अधिक दिख रही है। यही वजह है कि धान में पानी की जरूरत अधिक होने के बाद भी किसान धान की फसल को करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे में अब जिले में धान का रकबा 45 हजार हेक्टेयर पर पहुंच गया है। इस बार कृषि विभाग ने धान का रकबा 45 हजार हेक्टेयर निर्धारित किया है।

26 हजार में बाजरा, 27 हजार हेक्टेयर रकबे में होगी उड़द

कृषि विभाग के मुताबिक जिले में धान के लिए 45 हजार हेक्टेयर रकबा निर्धारित किया है। इसके बाद सबसे ज्यादा बोनी वाली फसल उड़द और बाजरा है। कृषि विभाग ने 26 हजार हेक्टेयर में बाजरा और 27 हजार हेक्टेयर

में उड़द की बोवनी का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह टारगेट कृषि विभाग ने गत वर्ष के मुकाबले थोड़ा बढ़ाकर लिया है। जिले के कुछ किसान मूंगफली और ग्वार भी करते हैं, क्योंकि इसमें भी अच्छी पैदावार होती है, इसलिए कृषि विभाग

ने मूंगफली के लिए 1700 हेक्टेयर रकबा, ग्वार के लिए 3 हजार हेक्टेयर रकबा, मक्का के लिए 4200 हेक्टेयर, अरहर के लिए 3200 हेक्टेयर, तिल के लिए 19 हजार हेक्टेयर का रकबा निर्धारित किया है।

खरीफ का लक्ष्य फसल हेक्टेयर

धान	45000
ज्वार	2000
मक्का	4200
बाजरा	26000
अरहर	3200
मूंग	4100
उड़द	27000
मूंगफली	1700
तिल	19000
सोयाबीन	20000
ग्वार	3000
कुल:	1 लाख 55 हजार 200 हे.

खरीफ सीजन के लिए फसलों का लक्ष्य प्रस्तावित कर लिया है। किसान भाई भी अपने खेतों में औपचारिकता गहरी जुलाई करें, ताकि खरीफ बोवनी में लाभ हो।
- पी शुक्ले, उपसंचालक, कृषि विभाग श्योपुर

इंदौर में 11 लाख पौधे लगाने का बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंदौर।

इंदौर में सफाई के बाद अब हरियाली को लेकर जन आंदोलन खड़ा करने की कवायद की जा रही है। इसके लिए इंदौर में 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। यह अभियान 7 से 14 जुलाई तक चलेगा। अभियान की लॉन्चिंग सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि 14 जुलाई को एक साथ 11 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी इंदौर आ रही है इस कार्यक्रम के लिए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को भी आमंत्रण दिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दे दी है। विजयवर्गीय ने बताया कि 51 लाख पौधे लगाना और उन्हें जीवित रखना हमारे लिए चुनौती है, लेकिन पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल के लिए भी हम अलग-अलग समितियां बनाएंगे। पौधे लगाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस अभियान के लिए शहर में प्रतिदिन 2 लाख गड्डे किए जा रहे हैं। अलग-अलग स्थानों को हमने चिन्हित किया है। कई समाजों के संगठनों ने हमने अभियान में जुड़ने के लिए संपर्क किया है। जो समाज जिस हिस्से में पौधे लगाएगा और उनकी देखभाल करेगा। उस हिस्से का नामकरण समाज के नाम से किया जाएगा। इसके अलावा रामायण के पात्रों के नामों पर शहर में अलग-अलग वन बनाए जाएंगे। विजयवर्गीय ने कहा कि शहर में इतने पौधे नहीं होने के कारण हमने पुष्पे, छत्रीसगढ़ से भी पौधे मंगाए हैं। इसके अलावा झाबुआ से श्रमिक भी आ रहे हैं, ताकि शहर में ज्यादा से ज्यादा गड्डे हो सकें।



पेटलावद की पहाड़ी पर लगे 20 हजार पौधे

झाबुआ। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पेटलावद के कचरा खांदन की 40 हेक्टर पर फैली पहाड़ी पर 20 हजार से ज्यादा गड्डे खोदे गए हैं। इसमें 20 हजार पौधे रोपे जाएंगे। वहीं पास के क्षेत्र में 50 हजार सोड बॉल भी डालेंगे। जिलेभर में अलग-अलग स्थानों पर खोदे गए गड्डों में 15 लाख से ज्यादा सीड बॉल डालेंगे। बॉल बनाने में कंचुआ खाद मिलाते हैं। एक बॉल में 2-3 बीज रखते हैं। खमैर, सीताफल, अमलतास व इमरली के बीज का उपयोग किया गया है। बॉल में एक से अधिक बीज होने से पौधे उगने की संभावना काफी अधिक होती है।



जल गंगा अभियान 16 जून तक चलाना जा रहा है। तालाब, कुएँ, बावड़ी आदि जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार व जनसहयोग से तालाब गहरीकरण के काम किए जा रहे हैं।
नेहा मौज, करलेक्टर, झाबुआ

जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जिले में विभिन्न स्थानों पर एक ही दिन में 20 लाख से अधिक सीड बॉल का रोपण किया गया जिससे जिले का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा रहा है। स्व-सहयता समूहों की दक्षियों ने 1.9 लाख बॉल तैयार की है। समूहों ने 1.32 लाख बॉल बनाई है।
जितेंद्र सिंह चौहान, सीईओ, जिए, झाबुआ

नदी से क्षेत्र की पहचान, इसे बचाकर पहचान को समृद्ध करेंगे: पटेल सुरक्षित भविष्य के लिए जल संरचनाओं को करेंगे पुनर्जीवित

प्रदेश में हरियाली अमावस्या तक साढ़े पांच करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य



भोपाल। जागत गांव हमारा

जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत नदियों के उद्गम स्थल की मानस यात्रा कर रहे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल तीन नदियों के उद्गम स्थल पहुंचे। मंत्री पटेल ने सिवनी जिले की ग्राम पंचायत शाखादेही स्थित बावनथडी नदी तथा बालाघाट जिले के कटंगी जनपद में अम्मा माई स्थित चंदन नदी और बारासिक्नी में कास नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचकर वृक्षारोपण, पूजन और जनसंवाद

किया। मंत्री पटेल ने कहा कि नदियों के सूखे उद्गमों के बीच बावनथडी के उद्गम स्थान पर स्रोत से बहती जलधारा आर्नोदित और आशान्वित करने वाली थी। यह हम सबका कर्तव्य है कि यह धारा अखिरल बनी रहे। नदी से क्षेत्र की पहचान होती है, इसे बचाकर आप अपने क्षेत्र को पहचान को समृद्ध करेंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षित भविष्य के लिए जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करना हमारा परम कर्तव्य है।

भोपाल। वर्षाकाल में हरियाली अमावस्या तक प्रदेश में कुल साढ़े 5 करोड़ पौधे रोपित किए जाएंगे। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज गंगा दशमी के अवसर पर दो दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिष्कार के समापन अवसर पर रामघाट पर आयोजित समारोह में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरचनाओं के संरक्षण का संकल्प साकार हो रहा है। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश की नदियां एवं जलाशय और अन्य जल स्रोत संरक्षित होकर प्रदूषणमुक्त रहें। प्रदेश में चले जल गंगा संवर्धन अभियान में 5 जून से आज तक

28 करोड़ लागत से शहरी क्षेत्र में 2700 से अधिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 26 करोड़ लागत से 2300 से अधिक संरचनाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हुआ है। उज्जैन के शहरी क्षेत्र की जल संरचना का भी सुधार कार्य हुआ है, जिसके बाद वह सुन्दर नजर आयेगी। प्रदेश में 212 नदियों का संरक्षण करने का संकल्प लिया गया है, जिसमें उद्गम से लेकर अन्तिम छोर तक संरक्षण का कार्य किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जल संरचनाओं के निकट पौधरोपण किया जाएगा।

जागत गांव हमारा के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमारा कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमारा के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 9425048589

“आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा”